आर.एन.आई. पंजीयन क्र. 39596/82 (डाक पंजीयन MP/IDC/1462/2016-2019)

साप्ताहिक

मालव अँचल

वर्ष 47 अंक 39 (प्रति रविवार) इंदौर, 16 जुन से 22 जुन 2024 पृष्ठ-8 मूल्य 3 रुपये

मणिपुर को लेकर केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने की उच्च स्तरीय बैठक

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार (17 जून) को मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख तपन डेका, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, सेना प्रमुख (नामित) लेफ्टिनेंट जनरल उपेन्द्र द्विवेदी, जीओसी थ्री कोर एचएस साही, मणिपुर के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह, मणिपुर के मुख्य सचिव विनीत जोशी, मणिपुर के डीजीपी राजीव बैठक में सिंह और असम राइफल्स के डीजी प्रदीप चंद्रन नायर मौजूद थे। बैठक में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह मौजूद नहीं थे। यह बैठक मणिपुर की राज्यपाल अनुसुइया उइके द्वारा अपने कार्यालय में गृह मंत्री से मुलाकात के एक दिन बाद हुई है और उन्हें उत्तर-पूर्वी राज्य की स्थितियों के बारे में जानकारी दी गई है। यह

बैठक गृह मंत्रालय में आयोजित की गई क्योंकि उत्तरी राज्य में ताजा हिंसा की सूचना मिली थी। पिछले साल 3 मई से, मणिपुर में दो समुदायों कुकी और मेइतेई के बीच झड़पें देखी गई हैं, जिसमें अब तक कम से कम 225 लोगों की जान चली गई है और लगभग 50,000 लोग विस्थापित हो गए हैं, जिनमें से कई अभी भी राहत केंद्रों में रह रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्य में पिछले कुछ हफ्तों में ताजा हिंसा देखी गई है, जिसमें मोरेह के पास एक स्कूल की इमारत में आग लगा दी गई और एक लापता व्यक्ति का सिर कटा शव मिला। पिछले हफ्ते, सशस्त्र उग्रवादियों ने कांगपोकपी जिले में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की उन्नत सुरक्षा टीम के काफिले पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें एक नागरिक चालक और एक सुरक्षा अधिकारी घायल हो गए। 10 जून को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि मणिपुर एक साल से शांति का इंतजार कर रहा है और इस मुद्दे को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भागवत ने चुनावी बयानबाजी से उबरने और देश के सामने आने वाली समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत पर जोर दिया।

नीट एग्जाम में एनटीए अधिकारी समेत कोई भी दोषी पाया गया तो कड़ी कार्रवाई होगी

भुवनेश्वर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट), 2024 के आयोजन में अनियमितताओं में यदि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के अधिकारी शामिल पाए गए तो सरकार उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। प्रधान ने विगत दिवस ओडिशा के संबलपुर की अपनी यात्रा के दौरान यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीट के आयोजन में दो प्रकार की गड़बड़ियां सामने आई हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कुछ छात्रों को कृपांक (ग्रेस मार्क) दिए गए थे क्योंकि वे निर्दिष्ट अवधि से कम समय दिए जाने से असंतुष्ट थे।

उन्होंने कहा कि सरकार ने कृपांक वापस ले लिए हैं और उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार 1,563 अभ्यर्थियों को पुनः परीक्षा का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा- दो स्थानों पर और भी अनियमितताएं सामने आई हैं। मैं छात्रों और अभिभावकों दोनों को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार ने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया है। हम इसे तार्किक परिणति तक ले जाएंगे। प्रधान ने कहा कि एनटीए के वरिष्ठ पदाधिकारियों समेत कोई भी अधिकारी यदि दोषी पाया जाता है तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफसख्त कार्रवाई होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने एनटीए में सुधारों की भी वकालत की। उन्होंने कहाए हालांकि एनटीए एक स्वायत्त इकाई है, लेकिन इसके कामकाज में बहुत से सुधारों की जरूरत है। सरकार इसे लेकर चिंतित है।

एक के बाद एक पांच समर्थकों की आत्महत्या, बिलखते परिवार को देख रो पड़ीं पंकजा मुंडे

मुम्बई/बीड। लोकसभा चुनाव में बीजेपी नेता पंकजा मुंडे की हार के बाद उनके समर्थकों को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में मुंडे समर्थकों का आत्महत्या का दौर जारी है। रविवार रात एक युवक संदीप शिरसाट ने भी आत्महत्या कर ली। पंकजा मुंडे ने सोमवार को आत्महत्या करने वाले युवक के परिवार से मुलाकात की। पंकजा मुंडे को देख परिवार फूट-फूट कर रोने लगा। अब तक पांच मुंडे समर्थकों की मौत हो चुकी है। पंकजा मुंडे लगातार आत्महत्या न करने की अपील कर रही हैं। हालांकि एक के बाद एक समर्थक आत्महत्या कर रहे हैं। ये देखकर उनका दिल भी दुखी हो रहा है। पंकजा मुंडे ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जीवन से हार मत मानो। मेरे कार्यकर्ता मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। कृपया ऐसा कदम न उठाएं। अपने बच्चों और परिवार को न छोड़ें। पंकजा मुंडे ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि मैं बहुत बहादुर इंसान हूं। हार के बावजूद मैं कभी असहज नहीं हूं। लेकिन इससे (समर्थकों के आत्महत्या करने) मुझे गहरा सदमा पहुंचा है और मैं खुद को दोषी महसूस करती हूं कि लोग अपनी जान दे रहे हैं। मैं आपको एक मौका दूंगी। मैं आपकी कसम खाता हूं। राजनीति में हार-जीत चलती रहती है। लोगों में हीन भावना पैदा होती जा रही है। पंकजा मुंडे ने कहा कि ये भावनाएं लोगों को विरोध के लिए प्रेरित कर रही हैं। दूसरी ओर बीड के आष्टी तालुका के चिंचवाड़ी के पोपट बैबसे ने एक पेड़ से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। रविवार को पंकजा मुंडे ने बैबसे परिवार से मुलाकात की। पंकजा को देखते ही बैबसे की पत्नी और बच्चे बिलख पड़े। ये देखकर पंकजा भी फूट-फूटकर रोने लगीं।

अब विधानसभा चुनावों की तैयारी में लगी भाजपा, कई राज्यों में बनाए प्रभारी

केन्द्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान को झारखंड की जिम्मेदारी

नई दिल्ली ।भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को प्रभारी नियुक्त किया। कुछ राज्यों में लोकसभा चुनाव में भारी झटका झेलने वाली भगवा पार्टी ने केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव को महाराष्ट्र के लिए राज्य चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान हरियाणा में पार्टी के चुनाव अभियान की देखरेख करेंगे, जबकि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को झारखंड के लिए चुनाव प्रभारी नियुक्त किया

गया है। जम्मू-कश्मीर के लिए, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर से पहले चुनाव कराने का निर्देश दिया है, भाजपा ने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को तैनात किया है। पार्टी ने इन राज्यों के लिए सह-प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। अश्विनी वैष्णव को महाराष्ट्र, बिप्लब कुमार देब को हरियाणा और हिमंत बिस्वा सरमा को झारखंड के लिए नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में इस साल के अंत में चुनाव होंगे। 2024 के लोकसभा चुनावों में, भाजपा ने महाराष्ट्र और हरियाणा में महत्वपूर्ण आधार खो दिया। महाराष्ट्र में कांग्रेस 17 में से 13 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि बीजेपी 28 में से सिर्फ 9 सीटें जीत सकी। एमवीए को राज्य की 48 में से 30 सीटें मिलीं, जबकि एनडीए केवल 17 सीटें हासिल कर सका। जबकि भाजपा की सीट का नुकसान महत्वपूर्ण था, पार्टी के महाराष्ट्र प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि महा विकास अघाड़ी (एमवीए) और एनडीए के बीच वोट का अंतर सिर्फ 0.3 प्रतिशत था। उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव में लोग भाजपा और उसके सहयोगियों को वोट देंगे क्योंकि वे जानते हैं कि एमवीए को सत्ता देने से कल्याणकारी परियोजनाएं रुक जाएंगी।

चिराग पासवान पर दिल हारी एक्ट्रेस, बोलीं- यार ये बंदा कितना क्यूट है, फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर छाए

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट के बाद से कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। चिराग पासवान को बिहार में पांच सीट दी गई थी और पांचों पर उन्होंने जीत हासिल की। चिराग की तस्वीरें और वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर छाये हुए हैं, जिन्हें देखकर फीमेल फैंस दीवानी हो गईं हैं। हर लड़की चिराग को अपना क्रश बता रही है। वहीं एक भोजपुरी एक्ट्रेस निशा दुबे भी चिराग पर दिल हार बैठी हैं। एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर सरेआम प्यार का इजहार कर दिया है। वीडियो में चिराग मंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण करते नजर आ रहे हैं। रील में सबसे पहले निशा दिखाई देती हैं और बैकग्राउंड में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक डायलॉग सुनाई देता है कि- औरत को आखिर चाहिए क्या? इसके बाद चिराग का वीडियो आ जाता है, जिसमें वो अपना नाम लेते दिख रहे हैं। इसके बाद चिराग का मासूम चेहरा और हंसी के कई शॉट्स दिख रहे हैं। पूरे वीडियो में गाना चल रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए निशा दुबे ने जो लिखा वो वायरल हो गया। फैंस इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं और अपना रिएक्शन दे रहे हैं।

संपादकीय

चुनाव आयोग और भाजपा की जान ईवीएम में?

भारत में ईवीएम की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद, लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की भूमिका, भारत सरकार द्वारा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में की गई मनमानी, भारतीय जनता पार्टी का 2014 के बाद ईवीएम का प्रेम, केंद्र में बहुमत की सरकार होने से न्यायपालिका का कमजोर होना, न्यायपालिका द्वारा चुनाव आयोग की संवैधानिक शक्तियों के आगे अपने आप को वास्तविकता से अलग-थलग कर लेने से यह विवाद बढ़ता ही जा रहा था। चुनाव आयोग और ईवीएम की निष्पक्षता को लेकर पिछले 5 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में यह लड़ाई लड़ी जा रही है। यह लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। दुनिया के आईटी,सोशल मीडिया इंडस्ट्री तथा दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी एलन मस्क ने ईवीएम मशीन की चिंगारी में आग लगाने का काम कर दिया है। एलन मस्क ने पोस्ट में लिखते हुए कहा, ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए। इसे इंसानों और एआई के माध्यम से आसानी से हैक किया जा सकता है। एलन मस्क के बयान के बाद राहुल गांधी का भी बयान आया। उन्होंने ईवीएम मशीन को ब्लैक बॉक्स की तरह बता दिया। चुनाव आयोग जिस तरह से ईवीएम मशीन और उसके सॉफ्टवेयर से संबंधित जानकारी को छुपा रहा है। जांच करने की इजाजत चुनाव आयोग किसी को नहीं देता है। चुनाव प्रक्रिया में कोई पारदर्शिता नहीं रह गई है। चुनाव आयोग की भी कोई जवाब देही नहीं है। चुनाव आयोग जो कहे, वही सही मान लिया जाता है। सूचना अधिकार कानून के तहत भी चुनाव आयोग मांगी हुई जानकारी नहीं देता है। चुनाव के कई महीने पहले से विपक्षी दल चुनाव आयोग से मिलने का समय मांग रहे थे। चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों को मिलने का और बैठक करने का समय भी नहीं दिया। इससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता भी प्रभावित हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन, सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों द्वारा किया गया। उस मामले में चुनाव आयोग ने चुप्पी साथ रखी थी। सत्ता पक्ष की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की। चुनाव लड़ने के लिए सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर मिले। इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की थी। चुनाव के दौरान सरकार और जाँच एजेंसियां विपक्षी दलों को घेरने का काम करती रहीं। विपक्षी दलों को चुनाव प्रचार करने से रोकने या बाधित करने के लिए तरह-तरह के प्रयास विभिन्न स्तरों पर किए गए। मतदान के बाद जिस तरह से फॉर्म 27 की जानकारी छुपाने का काम किया है। मतदान का आंकड़ा छुपाया गया। कहीं मतदान से ज्यादा, कहीं मतदान से कम मतगणना हुईं। ईवीएम मशीन में डाले गए वोट का मतगणना से मिलान नहीं हुआ। मतदाता पर्चियां को गिनने से चुनाव आयोग निरंतर इनकार करता रहा। जिसके कारण चुनाव आयोग, ईवीएम मशीन, वीवीपेट की पर्चियां सभी शक के दायरे में हैं। मतगणना के दौरान सत्ता पक्ष के दबाव में काम करने के भी कई आरोप सामने आए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में आम जनता, राजनीतिक दलों के नेताओं, दुनिया भर के राजनेताओं और कारोबारियों ने भारत मे हुए चुनाव की स्थिति का आकलन किया है। भारत में नियम और कानून का पालन हो रहा है या नहीं। इसे वैश्विक दुनिया बड़ी गंभीरता के साथ देखती है। एलन मस्क के बयान से अब ज्यादा दिनों तक ईवीएम मशीन से मतदान कराना चुनाव आयोग के लिए संभव नहीं होगा। चुनाव में पारिदर्शिता लानी ही होगी। मुंबई में शिवसेना शिंदे गुट के सांसद की 48 वोटो से जो जीत हुई है। निर्वाचन अधिकारी वंदना सूर्यवंशी और जीते हुए सांसद के रिश्तेदार द्वारा मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन का उपयोग करने के सबूत मिलने के बाद यह मामला भी तूल पकड़ने लगा हैं। 10 बरस के बाद विपक्ष पहले की तुलना में मजबूत हुआ है। विपक्ष भी अब न्यायपालिका में अपने हितों की लड़ाई लड़ना सीख गया है। न्यायपालिका के ऊपर भी अपने अस्तित्व को बचाए रखने का दबाव है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के वकीलों ने चुनाव आयोग और ईवीएम मशीन की गड़बड़ियों को लेकर न्यायपालिका के अंदर अपना पक्ष बड़ी मजबूती के साथ रख रहे हैं। इन सारी स्थितियों को देखते हुए संभावना बनने लगी है।

फिर आतंकी हमलें, कायम हो शांति का उजाला

ललित गर्ग

यह आशंका सच साबित हो रही है कि भाजपा को पूर्ण बहुमत न मिलने पर कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ेंगी एवं पाकिस्तान पोषित आतंकवाद फिर से फन उठाने लगेगा। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान से पाकिस्तान बौखलाया है। इसी का परिणाम है लगातार हो रहे आतंकी हमलें। इन हमलों ने आंतरिक सुरक्षा के लिये नये सिरे से चुनौती पैदा की है। जम्मू में रियासी, कठुआ और डोडा में चार दिनों में चार आतंकी हमले चिन्ता का बड़ा कारण बने है। रविवार को रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस के चालक पर हुए हमले के बाद बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई थी। जिसमें नौ श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। फिर कठुआ व डोडा में हुए आतंकी हमलों में एक जवान और दो आतंकवादी मारे गए हैं। लम्बे समय की शांति, अमन-चैन एवं खुशहाली के बाद एक बार फिर कश्मीर में अशांति एवं आतंक के बादल मंडराये हैं। धरती के स्वर्ग की आभा पर लगे ग्रहण के बादल छंटने लगे थे कि एक बार फिर कश्मीर को अशांत करने की कोशिशें तीव्र होते हुए दिख रही है। केन्द्र में गठबंधन वाली मोदी सरकार के सामने यह एक बड़ी चुनौती है।

इन आतंकी घटनाओं को केन्द्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई और हथियार भी बरामद हुए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गुरुवार को प्रधानमंत्री ने गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल व सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक की है। इसमें आतंकवाद की नई चुनौती से मुकाबले की रणनीति पर विचार हुआ है। दरअसल, नई सरकार बनने की प्रक्रिया के दौरान हुए इन हमलों में पाक की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन पाकिस्तान यह बड़ी भूल कर रहा है, क्योंकि मोदी सरकार की दृढ़ता एवं साहस को चुनौती देना इतना आसान नहीं है। फिर भी लगातार हुए आतंकी हमले चिंता तो बढ़ा ही रहे हैं। एलओसी से लगते जम्मू के इलाके में आतंकवादी घटनाओं का बढ़ना गंभीर हैं, चिन्ताजनक है। मारे गये दो आतंकवादियों के पास से पाकिस्तानी हथियार व सामान की बरामदगी बताती है कि पाकिस्तान सत्ता प्रतिष्ठानों की मदद से यह आतंक का खेल फिर शुरू कर रहा है। कहीं न कहीं दिल्ली में बनी गठबंधन सरकार को यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि पाक पोषित आतंकवादी जम्मू-कश्मीर में शांति एवं अमन को कायम नहीं रहने देंगे।

मैंने चुनाव से पूर्व अपनी एक सप्ताह की कश्मीर यात्रा में देखा कि केन्द्र सरकार ने कश्मीर में विकास कार्यों को तीव्रता से साकार किया है, न केवल विकास की बहुआयामी योजनाएं वहां चल रही है, बल्कि पिछले 10 सालों में कश्मीर में आतंकमुक्त करने में भी बड़ी सफलता मिली है। बीते साढ़े तीन दशक के दौरान कश्मीर का लोकतंत्र कुछ तथाकथित नेताओं का बंधुआ बनकर गया था, जिन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिये जो कश्मीर देश के माथे का ऐसा मुकुट था, जिसे सभी प्यार करते थे, उसे डर, हिंसा, आतंक एवं दहशत का मैदान बना दिया। लेकिन वहां विकास एवं शांति स्थापना का ही परिणाम रहा कि चुनाव में लोगों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेकर लोकतंत्र में अपना विश्वास व्यक्त किया। कहा जा सकता है कि राज्य में लोकतंत्र को मजबूत होते देख बौखलाहट में ये आतंकवादी हमले किये जा रहे हैं। दरअसल, केंद्रशासित प्रदेश का शांति-सुकून की तरफ बढ़ना आतंकवादियों की हताशा को ही बढ़ाता है। हाल के दिनों में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटकों का घाटी में आना और लोकसभा चुनाव में बंपर मतदान सीमा पार बैठे आतंकियों के आकाओं को रास नहीं आया है।

जम्मू के इलाके में आतंकी घटनाओं में वृद्धि शासन-प्रशासन के लिये गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। इन हमलों में पाकिस्तान की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। उल्लेखनीय है कि रविवार को हुए हमले की जिम्मेदारी जहां लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी गुट टीआरएफ ने ली तो डोडा में हुए हमले की जिम्मेदारी पाक पोषित जैश-ए-मोहम्मद के एक गुट कश्मीर टाइगर्स नामक आतंकी संगठन ने ली है। बहरहाल, भारतीय सेना व सुरक्षा बल आतंकवादियों को भरपूर जवाब दे रहे हैं। लेकिन इस माह के अंत में शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा का निर्बाध आयोजन सुरक्षा बलों के लिये बड़ी चुनौती होगी। जिसको लेकर विशेष चौकसी बरतने की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर हाल के आतंकी हमले केंद्र सरकार व राज्य प्रशासन को भी आत्ममंथन का मौका देते हैं।

तीन दशकों से कश्मीर घाटी दोषी और निर्दोषी लोगों के खून की हल्दीघाटी बनी रही है। लेकिन वर्ष 2014 के बाद से, नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से वहां शांति एवं विकास का अपूर्व वातावरण बना है। गठबंधन की केन्द्र सरकार के सामने अब बड़ा लक्ष्य है वहाँ आतंक से अमन-चैन तक लाने के चले आ रहे मिशन को सफल करने का, लोकतंत्र को सशक्त बनाने का, विकास के कार्यक्रमें को गति देने का एवं कश्मीर के लोगों पर आयी मुस्कान को कायम रखने का। बेशक यह कठिन और पेचीदा काम है लेकिन राष्ट्रीय एकता और निर्माण संबंधी कौन-सा कार्य पेचीदा और कठिन नहीं रहा है? इन कठिन एवं पेचीदा कामों को आसान करना ही तो नरेन्द्र मोदी एवं उनकी सरकार का जादू रहा है। अब गठबंधन सरकार में भी वे अपने इस जादू को दिखाये।

इन आतंकी हमलों ने अनेक प्रश्न खड़े किये हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि कश्मीर की जनता क्यों राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़ नहीं पा रही है? क्या कश्मीरी लोगों में नई व्यवस्था में अपने अधिकारों की सुरक्षा व संपत्ति के अधिकारों को लेकर मन में संशय की स्थिति में वृद्धि हुई है? हमें यह तथ्य स्वीकारना चाहिए कि किसी भी राज्य में आतंकवाद का उभरना स्थानीय लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकता। वहीं यह भी हकीकत है कि कश्मीरी जनमानस का दिल जीतना शक्ति से नहीं बल्कि उनके अनुकूल नीतियां बनाने व लोकतंत्र की बहाली से ही संभव है। अब कश्मीर में आतंक का अंधेरा नहीं, शांति का उजाला होना ही चाहिए। आए दिन की हिंसक घटनाएं आम नागरिकों में भय का माहौल ही बनाती हैं। माना कि रोग पुराना है, लेकिन ठोस प्रयासों के जरिए इसकी जड़ का इलाज होना ही चाहिए। कश्मीरियों में अपनी सुरक्षा के प्रति भरोसा जगाना सरकार की पहली जिम्मेदारी है। घाटी में सक्रिय आतंकियों के खात्मे में सुरक्षा तंत्र ने काफी कामयाबियां हासिल की हैं। अब जरूरत है खुफिया तंत्र को दूसरी तरह की चुनौतियों का सामना करने को तैयार एवं सक्षम किया जाये। घाटी में हालात सुधरने के केंद्र सरकार के दावों की सत्यता इसी से परखी जाएगी कि घाटी में अल्पसंख्यक पंडित और प्रवासी कामगार खुद को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। वास्तव में देखा जाये तो असली लड़ाई कश्मीर में बन्दूक और सन्दूक की है, आतंकवाद और लोकतंत्र की है, अलगाववाद और एकता की है, पाकिस्तान और भारत की है। शांति का अग्रदूत बन रहा भारत एक बार फिर युद्ध के जंग की बजाय शांति प्रयासों एवं कूटनीति से पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाये, यह अपेक्षित है।

पाकिस्तान एक दिन भी चुप नहीं बैठा, लगातार आतंक की आंधी को पोषित करता रहा, अपनी इन कुचेष्ठाओं के चलते वह कंगाल हो चुका है, आर्थिक बदहाली में कटोरा लेकर दुनिया घूम आया, अब कोई मदद को तैयार नहीं, फिर भी उसकी घरेलू व विदेश नीति 'कश्मीर' पर ही आधारित है। कश्मीर सदैव उनकी प्राथमिक सूची में रहा। पाकिस्तान जानता है कि सही क्या है पर उसकी उसमें वृत्ति नहीं है, पाकिस्तान जानता है कि गलत क्या है पर उससे उसकी निवृत्ति नहीं है। कश्मीर को अशांत करने का कोई मौका वह खोना नहीं चाहता। आज के दौर में उठने वाले सवालों में ज्यादातर का जवाब गठबंधन की मोदी सरकार को ही देना है, उसे सटीक जबाव देकर आतंकियों के मनसूबों को ढ़ेर करना होगा, पडोसी देश की गर्दन को एक बार फिर मरोड़ना होगा। यह बात भी सही है कि इस मसले को दलगत राजनीति से दूर रखना होगा।

प्रिंसेस स्टेट कॉलोनी के प्लाटधारकों की समस्याओं का होगा शीघ्र निराकरण

दोषियों के विरुद्ध होगी कार्रवाई : कलेक्टर आशीष सिंह

इंदौर।कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर प्रिंसेस स्टेट कॉलोनी के प्लाट धारकों को की समस्याओं का शीघ्र एवं प्राथमिकता के साथ निराकरण होगा साथ ही दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

प्रिंसेस स्टेट कॉलोनी के संबध में प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु जिला कलेक्टर इंदौर के निर्देशानुसार संयुक्त कलेक्टर सुश्री रोशनी वर्धमान की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय गठित समिति के द्वारा जांच की गई जिसमें सभी शिकायतकर्ताओं की शिकायतों का प्राथमिकता से परीक्षण किया गया । जहां कुछ व्यक्तियों के द्वारा दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए जिन्हें रजिस्ट्री होने के बावजूद भी मौके पर कब्जा प्राप्त नहीं हो पा रहा है। रहवासी संघ ने भी कुछ सदस्यों की सूची उपलब्ध कराई जिनके द्वारा पूर्ण भुगतान करने के बाद भी उनकी रजिस्ट्री नहीं कराई जा रही है जो कि जांच में भी सत्य पाया गया है। रहवासी संघ के कुछ और सदस्यों द्वारा एक और सूची उपलब्ध कराई गई थी जिनके द्वारा आंशिक भुगतान कर दिया गया था और वे व्यक्ति पूर्ण भुगतान भी करना चाहते हैं, लेकिन कालोनाइजर के कार्यालय बंद होने से ना तो रजिस्ट्री हो पा रही है और ना ही कोई अन्य प्रक्रिया । इसके संबध में भी गठित समिति द्वारा जांच की गई जो कि सही पाई गई है। जाँच में कालोनाईजर के द्वारा कार्यालय बंद कर दिया जाना भी सही पाया गया है। रहवासी संघ द्वारा डबल रजिस्ट्री की भी शिकायत की गई थी। जाँच अनुसार 12 व्यक्ति ऐसे पाये गये जिनको एक ही प्लाट की डबल रजिस्ट्री कर दी गई है। यही नहीं, जाँच के दौरान अन्य भी विवाद सामने आये जिसके अनुसार कॉलोनी की भूमि पर नक्शा बटांकन को लेकर विवाद है एवं इसी नम्बर पर किसान के द्वारा स्वयं के नाम टीएनसीपी कराकर एवं कालोनाईजर (अरूण डागरिया एवं महेन्द्र जैन) के नाम पॉवर अर्टनी करने के कारण कालोनाईजर के द्वारा भी अलग अलग रजिस्ट्री कर दी गई है, जिसके कारण व्यक्तियों को कब्जा प्राप्त नही हो पा रहा है ।

कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा तथ्यों को तत्काल संज्ञान में लेकर संबंधित कॉलोनाईजर के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है । दंडात्मक कार्यवाही के साथ साथ ऐसे सभी शिकायतकर्ताओं को जिनके द्वारा पूर्व में भुगतान किया गया था,उन्हें भुगतान अनुसार प्लॉट पर कब्जा दिलाये जाने की कार्यवाही भी जिला प्रशासन द्वारा प्राथमिकता से की जा रही है। सभी प्लॉट धारकों/ रजिस्ट्री धारकों एवं अन्य सभी जिनके साथ किसी भी प्रकार की कोई धोखा धड़ी सिद्ध होती है उनके विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है, प्रिंसेस स्टेट कालोनी के सभी प्लॉट धारकों की शिकायतों का निराकरण के लिये निरंतर कार्यवाही की जा रही है।

निगम का स्वयं का होगा ई पोर्टल, शासन ने दी मंजूरी

नागरिकों मिलेगी बेहतर सुविधा और होगा राजस्व वसूली संग्रहण कार्य सुगम

इंदौर। नगर निगम इंदौर को एक बड़ी सफलता मिली है। महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव और आयुक्त श्री शिवम वर्मा के निरंतर प्रयासों से मध्य प्रदेश शासन ने नगर निगम इंदौर को अपना स्वयं का ई पोर्टल बनाने की मंजूरी प्रदान की है। यह निर्णय नगर निगम इंदौर की राजस्व वसूली को सुगम बनाने और नागरिकों को हो रही समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से लिया गया है। निगम का ई पोर्टल आधुनिक होकर वर्तमान समय में अधिक से अधिक नागरिकों को सुविधा प्राप्त हो सके इस दृष्टि से बनाया जाएगा। शासन का ई नगर पालिका पोर्टल लंबे समय से तकनीकी दिक्कतों से जूझ रहा था, जिससे न केवल राजस्व वसूली प्रभावित हो रही थी, बल्कि नागरिकों को भी कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था ई नगर पालिका के कारण नगर निगम के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान भी समय पर नहीं हो पा रहा था। पोर्टल के बार-बार बंद होने और तकनीकी गलतियों के कारण नगर निगम की सेवाओं को समय पर प्राप्त करना नागरिकों के लिए एक चुनौती बन गया था। महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि निगम का यह पोर्टल नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा और हमारी राजस्व वसूली की प्रक्रिया को भी सरल और सशक्त बनाएगा।

आयुक्त श्री शिवम वर्मा ने बताया कि नए ई पोर्टल के माध्यम से नगर निगम की सभी सेवाओं को एकीकृत किया जाएगा, जिससे सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और नागरिकों को त्वरित और प्रभावी समाधान प्राप्त होंगे। इस पहल के साथ, इंदौर नगर निगम अब अपने नागरिकों को और भी बेहतर और सुगम सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होगा, जिससे शहर के समग्र विकास में योगदान मिलेगा और निगम को अपने सभी काम समय पर करने में आसानी और सुविधा होगी।

बढ़ती डिमांड के कारण 5 हजार साइकिलें और खरीदेगा एआईसीटीएसएल

इंदौर। साइकिलों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए माय बाइक योजना के तहत 5 हजार बाइकें और खरीदने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि यह 5000 वहां शीघ्र ही एआईसीटीएसएल को प्राप्त हो जाएंगे और इन्हें विभिन्न स्टैंड पर रख भी दी जाएंगी। वर्तमान में 2 हजार साइकलें 108 स्टैंडों से चलाई जा रही है। रोजाना एआईसीटीएसएल ऑफिस में डिमांड आने से निगम ने यह निर्णय लिया है।

जानकारी अनुसार पर्यावरण को सुधारने और बेहतर स्वास्थ्य के लिए करीब चार साल पहले स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में निगम माय बाइक योजना लेकर आया था। योजना को शुरुआती दिनों में युवा नहीं मिल रहे थे, लेकिन धीरे-धीरे युवाओं की संख्या बढ़ती चली गई।स्थिति यह है कि कई स्टैंडों पर लोग घंटों बाइक के लिए इंतजार करते हैं, बाइक नहीं मिलने पर अन्य लोकसेवा वाहनों से सफर करना मजबूरी बन जाता है। न्यूनतम किराया एक रुपए प्रतिघंटा होने से बच्चे भी इसे दिनभर चलाते रहते हैं। टूट-फूट होने पर साइकल को सुधरवाना भी नहीं पड़ता है। इसे देखते हुए निगम अब स्टैंडों की संख्या के साथ ही साइकलें भी ज्यादा रखेगा, ताकि डिमांड पूरी की जा सके। इसी क्रम में एआईसीटीएसएल ने चिड़ियाघर में आने वाले दर्शकों के लिए 10 साइकिलें शुरू की थी। यहां दो सीट वाली साइकिलें भी दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है। लगातार दर्शकों का साइकलों के प्रति रुझान बढ़ने से चिड़ियाघर प्रबंधन ने भी 5 साइकलों की डिमांड रखी है। साइकिलों के लिए निगम ने टैंडर बुलाए हैं। टैंडर के बाद सबसे पहले चिड़ियाघर में साइकिलें भेजी जाएगी।

काली मिट्टी के बेस पर बनाई रोड के जिम्मेदार अधिकारियों पर अब तक कार्रवाई नहीं

प्रेमसुख टॉकीज से चंद्रभागा ब्रिज तक बनाए स्मार्ट सड़क

इंदौर। काली मिट्टी के बेस पर बनाई गई जवाहर मार्ग स्थित प्रेमसुख टॉकीज से चंद्रभागा ब्रिज तक की सड़क के जिम्मेदार अधिकारियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस सड़क का निर्माण स्मार्ट सिटी कंपनी ने किया है। इस सड़क की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी डीपीआर तक नहीं बनाई गई है। स्मार्ट सिटी कंपनी का शहर में इससे स्मार्ट वर्क और शायद ही कोई दूसरा होगा। इस सड़क के निर्माण पर 12 करोड़ से अधिक लोकधन खर्च किया गया है। इसके बाद भी इस सड़क की स्पेशिफिक डीपीआर नहीं बनाई गई है। यह सड़क को रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा बताया जा रहा है। इसका बेस बनाने में 1 मीटर से अधिक काली मिट्टी भी भरने की बात सामने आई है। रहवासियों ने सड़क के बेस में 1 मीटर से भी अधिक काली मिट्टी भरने की शिकायत निगम कमिश्नर से लेकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक की है।

जानकारी अनुसार जवाहर मार्ग के ट्रैफिक का लोड कम करने के लिए जवाहर मार्ग से चंद्रभागा ब्रिज तक यह सड़क बनाई जा रही है। इस सड़क पर 12 करोड़ से अधिक लोकधन खर्च किया है। इस सड़क को बनाने के लिए स्मार्ट सिटी कंपनी के इंजीनियर और नगर निगम इंजीनियरों ने शुरू से ही मनमानी की है। सड़क बनाने के लिए वास्तविक डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) की कापी जब स्मार्ट सिटी कंपनी में आरटीआई आवेदन लगाकर मांगी तो उनके द्वारा जो कॉपी दी गई है उसमें स्पेशिफिक सड़क के बारे में डीपीआर न होते हुए कान्हा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की डीपीआर है। इस बारे में स्मार्ट सिटी कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि जो डीपीआर है वह दे रहे हैं। यह सड़क का रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। इससे एक यह प्रश्न उठना लाजिमी है कि 12 करोड़ से अधिक की सड़क बनाई जा रही है और इसकी डीपीआर ही नहीं बनाई गई है। मामले में यह भी बात सामने आई की करीब एक वर्ष पूर्व एक व्यक्ति ने डीपीआर की कॉपी मांगी थी तो उसे आरटीआई के तहत अलग दस्तावेज प्रदान किए गए हैं।

80 फीसदी कम हो चुका है सड़क का

जवाहर मार्ग से चंद्रभागा ब्रिज तक बनाई जा रही यह सड़क का 80 फीसदी कार्य पूर्ण हो चुका है। सड़क के एक हिस्से में तो ट्रैफिक भी दौड़ना शुरू हो गया है। सड़क के मध्य में स्थित एक मंदिर के कारण पूर्ण सड़क बनने में बाधा आ रही है।

दो आवेदकों को आरटीआई में दी डीपीआर की अलग-अलग कॉपी

करीब 1 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति ने आरटीआई के तहत सड़क की डीपीआर की कॉपी मांगी थी। उसे जो दस्तावेज दिए गए वह अन्य दस्तावेज हैं। वर्तमान में करीब एक महीना पूर्व भी एक आवेदक ने इसी सड़क की डीपीआर कि जब कॉपी मांगी तो उसे अन्य दस्तावेज दिए गए हैं। दोनों ही दस्तावेज सड़क की डीपीआर न होते हुए अन्य दस्तावेज प्रतीत होते हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या सड़क बनते बनते डीपीआर भी बदल गई, जबकि सड़क की स्पेशिफिक डीपीआर दोनों ही दस्तावेज में नहीं है।

प्रेमानंद महाराज का पंडित प्रदीप मिश्रा पर गुस्सा हो गया ठंडा?

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने निभाई बड़ी भूमिका : सूत्र

भोपाल। राधारानी पर टिप्पणी को लेकर कथावाचक पं. प्रदीप मिश्रा वृंदावन के संतों के निशाने पर थे। चर्चित संत प्रेमानंद महाराज जी ने इस टिप्पणी के बाद प्रदीप मिश्रा को आक्रोश में बहुत कुछ कहा था। प्रेमानंद महाराज जी ने यहां तक कह दिया था कि तुम किसी काम के नहीं रहोगे। इसके बाद पं. प्रदीप मिश्रा सफाई दे रहे थे। साथ ही उनसे माफी मांग रहे थे। अब मीडिया में खबरें आ रही हैं कि इस विवाद का पटाक्षेप हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेमानंद महाराज जी और कथावाचक पं. प्रदीप मिश्रा की सुलह कराई है।

प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद महाराज में फोन पर बात

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने तीन दिन पहले ओंकारेश्वर में कथा के दौरान पं. प्रदीप मिश्रा से बात की थी। दोनों की मुलाकात होटल के कमरे में हुई थी। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच राधारानी विवाद पर भी बात हुई थी। इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने दोनों में सुलह की पहल की। उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी से फोन पर प्रदीप मिश्रा से बात कराई। इसके बाद महाराज जी का गुस्सा शांत हुआ है।

नर्क जाओगे तुम

दरअसल, राधारानी को लेकर वीडियो आने के बाद वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज गुस्से से तमतमा गए थे। वह इस टिप्पणी को लेकर तू तड़ाक पर उतर आए थे। साथ ही कह दिया था कि राधा जी के बारे में ऐसी बात करते हो, तुम्हें नर्क में जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। साथ ही गुस्से में प्रेमानंद जी महाराज ने कहा था कि तुम्हारा सत्यानाश हो गया। श्रीजी के चरणों में आकर साष्टांग दंडवत माफी मांगो।

ये था पूरा विवाद

पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि राधा जी बरसाने की नहीं है। वह उनके पिता जी का कचहरी था। वह साल में एक बार कचहरी आती थीं। उनके पति का नाम अनय घोष है। वह रावल गांव की रहने वाली थीं। साथ ही प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि वह भगवान श्रीकृष्ण की पत्नी नहीं है। इसी वीडियो के सामने आने के बाद विवाद की शुरुआत हुई थी।

प्रदीप मिश्रा ने मांगी थी माफी

वीडियो सामने आने के बाद प्रदीप मिश्रा का जगह-जगह विरोध होने लगा। साथ ही वृंदावन के संतों में भी उनके खिलाफ नाराजगी बढ़ने लगी। इसके बाद एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रदीप मिश्रा ने प्रेमानंद महाराज जी से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि यह वीडियो 14 साल पुराना है, जिसे तोड़ मरोड़कर परोसा जा रहा है। प्रेमानंद महाराज के तल्ख तेवर के आगे प्रदीप मिश्रा बैकफुट पर थे और लगातार सफाई दे रहे थे।

दोनों के बीच हो गई सुलह

अब बताया जा रहा है कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की पहल के बाद दोनों संतों में सुलह हो गई है। प्रेमानंद महाराज जी के आक्रोश वाले वीडियो एक्स से हटे हैं। वहीं, प्रदीप मिश्रा ने भी चुप्पी साध ली है। ऐसे में अब मामला ठंडा होने की संभावना है। अब दोनों ही तरफ से कोई प्रतिक्रिया या नया वीडियो सामने नहीं आया है।

सब्सिडी के लिए किसान नहीं करा पा रहे पंजीयन एमपीएफएसटीएस पोर्टल पड़ा ठप

भोपाल।सरकार ने उद्यानिकी फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिए कई तरह की सब्सिडी की व्यवस्था की है। लेकिन विडंबना यह है कि सब्सिडी के लिए पंजीयन करने वाला पोर्टल पिछले कई दिनों से बंद पड़ा है। इससे प्रदेश के लाखों किसान परेशान हो रहे हैं, लेकिन उद्यानिकी विभाग के अफसरों को इसी सुध ही नहीं है। बता दें कि मप्र में उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल 36 लाख हेक्टेयर है, इस पोर्टल के बंद होने से इन क्षेत्र में कृषि और किसानों हर स्तर पर शत-प्रतिशत प्रभावित होंगे। वहीं सरकार की किसान हितैषी विभिन्न योजना के तहत इस पोर्टल के माध्यम से कोल्ड स्टोरेज, ड्रिप, ड्रिप स्प्रिंकलर, पाली हाउस, शेडनेट हाउस, वाक इन टनल, ट्रैक्टर,जैसे कृषि उपकरणों के लिए सब्सिडी दी जाती है। गौरतलब है की प्रदेश में सरकार द्वारा उद्यानिकी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस कारण बड़ी संख्या में किसान इस ओर आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन उद्यानिकी फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी दिलाने वाला पोर्टल पिछले कई दिनों से बंद है। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में किसानों की योजनाओं का क्रियान्वयन मप्र फॉर्मर सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम (एमपीएफएसटीएस) पोर्टल में पंजीयन के माध्यम से होता है। पोर्टल में किसानों का पंजीयन 7 जून से शुरू हुआ और 11 जून को पोर्टल बंद हो गया। जिससे किसान सब्सिडी के लिए पंजीयन से वंचित हो गए हैं। वहीं किसानों की फसल लेने की (बोवनी) की शुरुआत 20 जून से होती है, इसके बावजूद पोर्टल में पंजीयन चालू करने के कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। 20 जून तक किसानों का चयन लाटरी के माध्यम से किया जाना है, लेकिन पोर्टल बंद होने से यह प्रक्रिया भी प्रभावित होगी।

50 प्रतिशत तक मिलती है सब्सिडी

सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम (एमपीएफएसटीएस) के अंतर्गत किसान विभिन्न योजना में पंजीयन कराकर सब्सिडी का लाभ लेते हैं। इसके तहत मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने एवं किसानों को विभिन्न प्रकार की योजना के लाभ प्रदान करना है। इसके तहत कृषि उपकरण और सिंचाई उपकरण के माध्यम से किसान अपनी फसल को बेहतरीन कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरणों पर इस योजना के तहत सरकार द्वारा 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। जून माह निकलने के बाद किसान अपने स्तर पर फसल की तैयारी कर लेता है, इसमें योजना के लाभ से किसान वंचित हो जाएगा।

मानसून सत्र के बाद हटेगा तबादलों से प्रतिबंध

भोपाल। प्रदेश में एक जुलाई के बाद सरकार तबादलों से लगभग 15 दिन के लिए प्रतिबंध हटा सकती है। पहले विधानसभा और इसके बाद लोकसभा चुनाव के कारण इस वर्ष प्रतिबंध लगा हुआ है। तबादला नीति घोषित करके विभागों को प्रशासनिक आधार पर तबादले करने का अधिकार विभागों को दिया जाएगा। तब तक मंत्रियों को जिला का प्रभार भी दे दिया जाएगा। इनके अनुमोदन से जिले के भीतर तबादले होंगे। अभी मुख्यमंत्री समन्वय के माध्यम से ही वे ही तबादले हो रहे हैं, जो आवश्यक हैं। सरकार आमतौर पर प्रतिवर्ष मई-जून में तबादलों पर से प्रतिबंध हटाती है। इसमें अधिकतम 20 प्रतिशत तबादले करने के अधिकार विभागीय मंत्रियों को मिलते हैं। विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव के कारण तबादलों पर रोक लगी थी।

अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं और जनप्रतिनिधियों से लेकर कर्मचारी संगठनों की मांग है कि कुछ दिनों के लिए तबादले पर लगी रोक को हटाया जाए। सूत्रों का कहना है कि एक जुलाई से विधानसभा का मानसून प्रारंभ होना है इस अवधि में तबादले करने से कार्य प्रभावित हो सकता है इसलिए सत्र समाप्त होने के बाद कुछ दिनों के लिए तबादलों पर लगी रोक हटाई जाएगी। इस अवधि में केवल वे ही तबादला मुख्यमंत्री कार्यालय से पूछ बिना नहीं होंगे, जिन्हें मुख्यमंत्री समन्वय से आदेश लेकर हटाया गया था। दरअसल, प्रतिबंध अवधि में तबादले केवल मुख्यमंत्री समन्वय के माध्यम से ही हो सकते हैं। उधर, छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को देखते हुए यहां तबादले आचार संहिता के प्रभावी रहने के दौरान चुनाव आयोग की अनुमति के बिना नहीं होंगे।

कलेक्टर-कमिश्नर, एसपी-आइजी बदलेंगे

उधर, सरकार कलेक्टर-कमिश्नर, एसपी-आइजी भी बदलेगी। इसको लेकर सामान्य प्रशासन और पुलिस मुख्यालय स्तर पर तैयारियां भी प्रारंभ हो गई हैं। अब जो जमावट होगी, वह आगामी दो वर्ष के हिसाब से की जाएगी ताकि निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हो सके। सूत्रों का कहना है कि मैदानी के साथ-साथ मंत्रालय स्तर पर भी अधिकारियों के दायित्व में परिवर्तन होगा।

18 करोड़ के घोटाले का नहीं मिला सुराग

फसल क्षतिपूर्ति घोटाले में निलंबित आरोपी बहाल

भोपाल।मप्र वाकई अजब है गजब है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि प्रदेश में किसानों की फसल के क्षतिपूर्ति में 18 करोड़ रूपए का घोटाला हुआ है। घोटाले के आरोप में अधिकारियों-कर्मचारियों को निलंबित भी किया गया और बाद में उन्हें बहाल भी कर दिया गया, लेकिन आज तक घोटाले का सुराग नहीं मिल पाया है। दरअसल, घोटाले की फाइल ही गायब कर दी गई है। प्रदेश 12 जिलों में फसल क्षतिपूर्ति की राशि में घोटाले का मामला महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट में उजागर हुआ था। ऑडिट में पता चला कि सीहोर, विदिशा, रायसेन, शिवपुरी, सतना, दमोह, देवास, छतरपुर, खंडवा, सिवनी, मंदसौर, आगर और श्योपुर में गबन किया गया है। इन जिलों में करीब 18 करोड की राशि का गबन किया गया था। कुछ जिलों में एफआईआर भी कराई गई, लेकिन आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई। सबसे बड़ी कार्रवाई देवास कलेक्टर ने एक साथ 39 पटवारियों को निलंबित कर की थी। बाद में 2 पटवारी एवं 2 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है।

गौरतलब है कि प्रदेश के सरकारी अमले को जहां पर भी मौका मिलता है, घोटाला करने से नहीं चूकते हैं फिर मामल आपदा का हो या किसी अच्छे अवसर का। ऐसे मामलों में सरकार से लेकर शासन तक ठोस कार्रवाई नहीं करता है, जिसकी वजह से ऐसे मामलों पर रोक नहीं लग पा रही है। यहाँ तक की अफसरों ने घोटाले से जुड़ी फाइल ही गायब कर दी है। ऐसा ही एक मामला है, किसानों की दी जाने वाली फसल क्षतिपूर्ति का। फसल नष्ट होने की वजह से जब प्रदेश का किसान गहरे संकट में था, तब जिम्मेदारों ने उनकी मदद के नाम पर जमकर मौज काटी। इस मामले का जब महालेखागार ने खुलासा किया तो पता चला कि इस घोटाले से संबंधित फाइलें ही गायब हैं। यह पूरा मामला एक दर्जन जिलों में 18 करोड का है। अहम बात यह है कि अधिकांश जिलों में जांच के नाम पर सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। इस पूरे में मामले में अब तक महज देवास जिले में कुछ ही आरोपियों पर कार्रवाई की गई है।

दूसरों के बैंक खातों में राशि डाली

दरअसल इसका खुलासा पिछले साल महालेखाकार की रिपोर्ट में हुआ था। इसके बाद कलेक्टरों ने जांच शुरु करवाई। इसका खुलासा उस समय हुआ, जब बीते साल महालेखाकार द्वारा विभिन्न जिलों से किसानों की क्षति पूर्ति के लिए आई राशि का ऑडिट किया गया। जिन किसानों के खातों में राशि डालनी थी, उनकी जगह दूसरों के बैंक खातों में राशि डाली गई। ऑडिट रिपोर्ट सामने आने के बाद राजस्व विभाग में हडकंप मच गया। आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में 200 से ज्यादा पटवारी एवं अन्य कर्मचारियों को निलंबित किया गया था, जो बाद में बहाल कर दिए गए। फसल क्षतिपूर्ति मामले में नाजिर शाखाओं से रिकॉर्ड गायब होने का मामला भी सामने आया है।

पीएमश्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा देवस्थलों के प्रति हमारी आस्था को जोड़ने का संकल्प है-मुख्यमंत्री डॉ यादव

››उज्जैन में बनेगा एयरपोर्ट, भारत सरकार ने दी मंजूरी›› मुख्यमंत्री डॉ यादव ने उज्जैन हेलीपैड से किया पीएमश्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा संचालन का शुभारंभ

भोपाल।मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि पीएमश्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा केवल श्री महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर नहीं है बल्कि हमारे आस्था के केंद्र ज्योतिर्लिंगों के प्रति देश और दुनिया में स्थित श्रद्धालुओं की आस्था को जोड़ने का संकल्प हैं। इस आनंद में आज हम सभी सहभागी बन रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उज्जैन में एयरपोर्ट बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ यादव आज उज्जैन स्थित पुलिस लाइन में पीएमश्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा के संचालन प्रारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कार्यक्रम में पीएमश्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा के तहत प्रारंभ हो रहे हैं हेलीकॉप्टर की विधिवत पूजा अर्चना की और हेलीकॉप्टर को हरी झंडी दिखाकर हवाई सेवा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने हेली सेवा के अंतर्गत प्रथम यात्री मुंबई से आई श्रीमती दिशा सिंह और उनके परिवार को विमान टिकट का वितरण किया। पहले चरण में भोपाल उज्जैन ओंकारेश्वर एवं इंदौर उज्जैन ओंकारेश्वर रूट पर यह हवाई सेवा प्रारम्भ की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आईआरसीटीसी पर इस सेवा की बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि प्रदेश में हवाई सेवा का विस्तार निरंतर

जारी रहेगा। आने वाले दिनों में हेलीकॉप्टर की संख्या और बढ़ाई जाएगी। जिसमें 16 -16 यात्री हवाई सेवा का लाभ ले सकेंगे। प्रदेश के मैहर, दतिया, ओरछा, अन्य धार्मिक, पर्यटन और ऐतिहासिक महत्व के देव स्थलों को भी हवाई यात्रा से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक उज्जैन उत्तर अनिल जैन कालूहेड़ा, विधायक सतीश मालवीय, महापौर मुकेश टटवाल, विवेक जोशी, बहादुर सिंह बोरमुंडला, अन्य गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, एसीएस राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव विमानन संदीप यादव, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा अन्य अधिकारीगण मौजूद थे।

उज्जैनवासियों ने पेश की सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन को पिछले दो दिनों में कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों की सौगातें मिली हैं। विकास का यह क्रम निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि विकास के लिए उज्जैनवासियों ने सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल पेश की हैं। केडी मार्ग चौड़ीकरण के लिए स्वेच्छा से धार्मिक स्थलों को पीछे करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ यादव ने उज्जैनवासियों को धन्यवाद दिया।

कान्ह का दूषित जल मां शिप्रा में नहीं मिलेगा

मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि विकास के मामले में उज्जैन नित्य नए आयाम स्थापित कर रहा है। मां शिप्रा शुद्धिकरण के संकल्प को पूरा करने के लिए कान्ह क्लोज डक्ट परियोजना का भूमिपूजन किया गया। जिसमें बड़े आकार की लाइन के माध्यम से पूरी कान्हा नदी की दिशा बदली जायेगी। जिससे मां शिप्रा में कान्ह का दूषित पानी नहीं आएगा। मां शिप्रा का जल शुद्ध बना रहेगा। प्रमुख सचिव विमानन संदीप यादव ने इस अवसर पर कहा कि हम सबके लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि उज्जैन से ओंकारेश्वर तक हेलीकॉप्टर के माध्यम से यात्रा का शुभारंभ आज होने जा रहा है। यह हेलीकॉप्टर 2 सीटर से 12 सीटर होंगे। इनका शुल्क 5000 रूपये निर्धारित किया गया है जो अत्यंत कम है। धार्मिक पर्यटन स्थलों की यात्रा अब और सुगम हो सकेगी। मुख्यमंत्री द्वारा एयर एंबुलेंस की शुरुआत भी मध्यप्रदेश में की गई है। जिसके अंतर्गत आयुष्मान कार्ड धारी और अन्य सामान्य नागरिक भी प्रदेश में उपचार प्राप्त करने के लिए अत्यंत कम समय में हवाई यात्रा कर सकेंगे। श्री यादव ने अपनी ओर से सभी को शुभकामनाएं दी।

उज्जैन को मिल रही नित्य नवीन सौगातें-सांसद श्री फिरोजिया

सांसद श्री अनिल फिरोजिया ने इस अवसर पर कहा कि धार्मिक पर्यटन के लिए हेली सेवा का आज उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा एअर टैक्सी की सेवा भी प्रारंभ की गई है। हम सभी के लिए आज आनंद का अवसर है कि उज्जैन में निरंतर विकास हो रहा है। पहले यहां सिर्फ सिंहस्थ के दौरान विकास के कार्य किए जाते थे। परंतु अब प्रतिदिन उज्जैन को नित्य नई सौगात मिल रही है । भगवान महाकालेश्वर के आशीर्वाद से उज्जैन का चौमुखीविकास हो रहा है। उज्जैन की दिशा और दशा दोनों बदल रही हैं। गत दिवस उज्जैन को 800 करोड रुपए से अधिक की कई सौगातें प्राप्त हुई हैं। उज्जैन से जावरा तक बनाए जाने वाले फोरलेन की डीपीआर बन चुकी है तथा शीघ्र ही काम प्रारंभ होगा। नागझिरी से नरवर तक फोरलेन बनाया जाएगा। उज्जैन शहर में भी कई मार्गों का चौड़ीकरण किया जा रहा है कई मार्ग फोरलेन बनाए जा रहे हैं। उज्जैन से ओंकारेश्वर तक के लिए हवाई यात्रा प्रारंभ हुई है।

उज्जैन के औद्योगिक विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लगभग 6000 करोड़ लगत का इंदौर उज्जैन सिक्स लेन मार्ग स्वीकृत किया गया है। दूसरी तरफ उज्जैन जावरा मार्ग जिसकी लागत लगभग 5000 करोड़ है, जो शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से लगभग 6000 करोड़ के काम प्रगतिरत हैं। उज्जैन में औद्योगिक विकास का क्रम निरंतर जारी है। विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में लगभग एक हजार एकड़ भूमि उद्योगों के लिए आवंटित की जा चुकी है। इसके अलावा एक हजार एकड़ और भूमि के लिए प्रस्ताव बनाया गया है। उज्जैन के औद्योगिक विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार होने की संभावना

सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस के पास कई मुद्दे

नर्सिंग कॉलेज, अतिथि शिक्षक और चयनित शिक्षकों को नियुक्ति न देने के अलावा आदिवासी अत्याचार भी मुद्दा

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार होने की आशंका है इसलिए कि विपक्ष के पास मोहन यादव सरकार को घेरने के कई ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे जनता से जुड़े हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए ऐसे कई मुद्दे उठाए और जनआंदोलनों का समर्थन किया जो मांगों से जुड़े हैं। अब वे इन मसलों को विधानसभा में उठाकर सरकार को घेरेंगे।

इनमें फर्जी नर्सिंग कॉलेज, अतिथि शिक्षक, चयनित शिक्षकों को नियुक्ति न देने संबंधी कई मुद्दे हैं। इसके अलावा 60 हजार करोड़ के निवेश से सीहोर जिले की आष्टा तहसील में प्रस्तावित एथेन क्रैकर परियोजना के विरोध पर भी सरकार की घेरेबंदी होगी। इसलिए कि

किसानों ने कह दिया कि मर जाएंगे, लेकिन प्लांट के लिए अपनी जमीन नहीं देंग। सत्र के दौरान कांग्रेस महिला, अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के ऊपर हुए अत्याचार की घटनाओं के साथ प्रदेश की आर्थिक स्थिति को भी मुद्दा बनाएगी।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इन मुद्दों को उठाने का इशारा भी पिछले दिनों कर दिया था। उन्होंने नर्सिंग कॉलेज वाले मसले के लिए सोशल मीडिया पर जनता से आह्वान भी किया है कि वे उन्हें दस्तावेज और जानकारियां भेजें ताकि मुद्दे को सार्थक तरीके से उठाया जा सके। सिंघार ने इसके लिए टोल फ्री नम्बर और ईमेल आईडी भी जारी किया है। इसके अलावा अतिथि शिक्षकों वाले मुद्दे पर भी नेता प्रतिपक्ष मुखर हैं। उन्होंने इन शिक्षकों को पूरे साल की नियुक्ति न देने को मुद्दा बनाया है और अब इसे विधानसभा में भी उठाएंगे। उन्होंने अपने एक्स एकाउंट पर सरकार को घेरते हुए लिखा था कि पिछले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इन शिक्षकों से जो मांग की थी, डॉ मोहन यादव ने उसे भुला दिया। एक जुलाई से 19 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र में कुल 14 बैठकें होंगी। मोहन सरकार इसमें अपना पहला पूर्ण बजट प्रस्तुत करेगी। यह साढ़े 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है। लोकसभा चुनाव के बाद होने वाले इस सत्र में परिणाम के असर की झलक भी दिखाई देगी।

जिला आबकारी प्रभारी समेत तीन उपनिरीक्षक निलंबित

भोपाल।रायसेन स्थित सोम शराब फैक्ट्री में बालश्रम मामला सामने आने के बाद सीएम मोहन ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के एक्शन मोड में आते ही आबकारी अधिकारियों पर निलंबन की गाज गिर गई।

कन्हैयालाल अतुलकर, प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी, मैसर्स सोम डिस्टलरीज प्राइवेट लिमिटेड, सेहतगंज को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही जिले के तीन आबकारी उप निरीक्षक को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उप निरीक्षक प्रीति शैलेंद्र उईके, शैफाली वर्मा और मुकेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि शराब फैक्ट्री में नाबालिग बच्चे काम करते पाए गए थे। जिसके बाद सीएम ने इस मामले को बेहद गंभीर बताते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए थे। शराब फैक्ट्री से 59 बच्चों का रेस्क्यू-रायसेन में मासूम बच्चों से एक शराब फैक्ट्री में काम करवाने का मामला सामने आया है। शनिवार दोपहर में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम ने यहां छापा मारा तो कई बच्चे काम करते मिले। मामला जिले में स्थित एक शराब फैक्ट्री का है।

जहां से राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने अपनी टीम के साथ 59 बाल मजदूरों का रेस्क्यू किया। इनमें 20 लड़कियां भी शामिल हैं। ये बच्चे रायसेन और भोपाल जिले के हैं। प्रियांक कानूनगो ने बताया कि बचपन बचाओ आंदोलन से शिकायत मिली थी कि फैक्ट्री में बच्चों से 15 से 16 घंटे तक काम कराया जा रहा है। मामला सामने आने के बाद जिला आबकारी प्रभारी कन्हैयालाल अतुलकर, उप निरीक्षक प्रीति शैलेंद्र उईके, उप निरीक्षक शैफाली वर्मा और उप निरीक्षक मुकेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है।

BOLLYWOOD UPDATE

माल्या की कैलेंडर गर्ल लीजा हेडन की कॉफी शॉप से खुली थी किस्मत

बॉलीवुड की फैशनिस्टा की बात हो और एक्ट्रेस लीजा हेडन की बात न हो ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। भले ही अब वह फिल्मों में कम नजर आ रही है, लेकिन वह सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ की हर छोटी-बड़ी अपडेट शेयर करती रहती हैं। 17 जून, 1986 को चेन्नई तमिलनाडु में जन्मीं लीजा मॉडल एक्टर होने के साथ-साथ फैशन डिजाइनर भी हैं। वह अपना 38वां जन्मदिन मना रही हैं। 'आयशा', 'रास्कल', 'क्वीन' जैसी फिल्मों में अपने दमदार किरदार से दर्शकों का दिल जीत चुकी है। लीजा फिल्मों में आने से पहले मॉडलिंग की दुनिया में भी खूब नेम फेम कमा चुकी हैं।

बनना चाहती थी योगा टीचर

लीजा हेडन शादी के बाद अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी है। वह तीन बच्चों की मां हैं। फिल्मों से दूर एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, वह अक्सर अपनी

तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं। एक्ट्रेस की फिटनेस मां बनने के बाद भी नहीं बदली है, जिसकी वजह है कि वो वर्कआउट करती हैं। लीजा हेडन योगा टीचर बनना चाहती थीं, लेकिन दोस्तों के कहने पर उन्होंने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया।

ऐसे मिली थी लीजा को पहली फिल्म

लीजा हेडन की बॉलीवुड में एंट्री बहुत फिल्मी स्टाइल में हुई थी। जी हां, एक्ट्रेस को बॉलीवुड में एंट्री अनिल कपूर की वजह से मिली थी। दरअसल एक कॉफी शॉप में अनिल कपूर ने लीजा हेडन को देखा, जिसके बाद उन्होंने फिल्म 'आयशा' के लिए उन्हें साइन कर लिया। कास बात तो ये थी कि उन्हें एक्टिंग नहीं आती थी, इसलिए वह फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ट्रेनिंग के लिए न्यूयॉर्क गईं थीं। बता दें कि साल 2016 में अपने बॉयफ्रेंड डिनो ललवानी से शादी करने के बाद से लीजा फिल्मों से दूर हैं।

इसके अलावा लीजा का ऋतिक रोशन के साथ वोग मैगजीन के जनवरी 2017 एडिशन के लिए कराया गया फोटोशूट भी लाइमलाइट में रहा है।

बकरीद पर स्वारा भास्कर ने वेजीटेरियन लोगों पर उठाए सवाल

बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस स्वरा भास्कर अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। वह जब भी कोई बयान देती हैं सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होता है। स्वरा देश-दुनिया के मुद्दों पर भी अपनी राय देती नजर आती हैं। पिछले दिनों स्वरा भास्कर ने कंगना रनौत के थप्पड़ कांड पर बयान

दिया था जिसके बाद वह जमकर चर्चाओं में आ गई थीं। वहीं अब फिर स्वरा भास्कर अपने हाल ही में दिए बयान की वजह से चर्चा में हैं।

बकरीद पर किया स्वरा ने ये सवाल दरअसल स्वरा भास्कर ने अपने ट्विटर एक्स पर बकरीद को लेकर एक ट्वीट शेयर किया है। जिसपर जमकर लोगों के रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। कुछ लोग तो स्वरा की जमकर तारीफ कर रहे हैं तो कई लोग स्वरा को ट्रोल करते नजर आ रहे हैं। वेजीटेरियन होने पर उठाए सवाल दरअसल स्वरा ने अपने ट्विटर एक्स पर वेजीटेरियन होने पर सवाल किए हैं। उन्होंने नलिनी उनागर नाम की फूड ब्लॉगर के वेजीटेरियन होने पर सवाल किए हैं। नलिनी अपने खाने की तस्वीरें शेयर करती हैं और लिखती हैं उन्हें वेजीटेरियन होने पर गर्व महसूस होता है। मेरी प्लेट आंसू, क्रूरता और पाप से फ्री है। स्वरा भास्कर का फूटा गुस्सा वहीं नलिनी के इस पोस्ट को जवाब देते हुए कहा कि- सच कहूं तो मुझे वेजीटेरियन लोगों की बात समझ नहीं आती है। आप लोगों की सारी डाइट गाय के नन्हे बछड़ों को उनकी मां के दूध से वंचित करके गायों को जबरन गर्भवती करके फिर बच्चों को उनसे अलग करके उनका दूध चुराने से बनती है। इसके अलावा आप जड़ वाली सब्जियां खाते हैं। जिससे पूरा पौधा खत्म हो जाता है। बेहतर होगा कि आप रिलैक्स करें क्योंकि आज बकरीद है।

काम नहीं मिल रहा है एक इंटरव्यू में स्वरा ने कहा कि उनके बेबाक अंदाज की वजह से उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा है। लोग उन्हें विवादित एक्टर के रूप में देखते हैं। उनका बेबाक होना उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर असर डालता है।

नेटफ्लिक्स ने घोषित किया द ग्रेट इंडियन कपिल शो का सीजन 2!

नेटफ्लिक्स द्वारा द ग्रेट इंडियन कपिल शो के दूसरे सीज़न की घोषना को सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हो जाइए। पहले सीज़न को दर्शकों से मिले बहुत प्यार और ज़बरदस्त कामयाबी के चलते, इसे दूसरे सीज़न के लिये रिन्यू किये जाने से यह साबित होता है कि नेटफ्लिक्स अपने दर्शकों को अनोखे और क्वालिटी प्रोग्राम लाने के लिए कमिटेड है। द ग्रेट इंडियन कपिल शो के मौजूदा सीज़न में सुपरस्टार आमिर खान, अभिनेता रणबीर कपूर और उनका परिवार, क्रिकेट हीरो रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर, अंतर्राष्ट्रीय पॉप आइकन एड शीरन और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बहुत सारे नामी गिरामी सितारे शामिल हुए। 22 जून को होने वाले फिनाले के साथ साथ, शो ने हर हफ़्ते दर्शकों को मस्ती और मनोरंजन से जोड़े रखा और शो में आये सेलिब्रिटी मेहमानों ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया! लॉन्च के बाद से भारत में नेटफ्लिक्स के टॉप दो शो में शामिल द ग्रेट इंडियन कपिल शो पांच हफ्तों तक ग्लोबल टॉप 10 नॉन-इंग्लिश टीवी लिस्ट में रहने वाली पहली भारतीय सीरीज़ है। सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा और राजीव ठाकुर ने हफ़्ते दर हफ़्ते शानदार प्रदर्शन किया, कपिल शर्मा ने एक के बाद एक धमाकेदार पंच दिए और अर्चना पूरन सिंह बड़ी शान से अपनी पसंदीदा कुर्सी पर जमी रहीं। इस सीरीज़ ने दर्शकों को पूरी तरह बाँधे रखा और इस तरह ये एक बेहतरीन हिट शो साबित हुआ । नेटफ्लिक्स कॉमेडी शैली के सबसे बेहतरीन और सबसे ज़्यादा वैरायटी वाले कंटेंट लाने के लिए प्रतिबद्ध है और सुनिश्चित करते हैं कि प्रोग्रामो में हर दर्शक के लिए कुछ न कुछ हो।अधिक जानकारी के लिए बने रहें,द ग्रेट इंडियन कपिल शो पर'!

गर्मियों में इन वजहों से बढ़ जाती है फूड पॉइजनिंग की समस्या, ऐसे करें बचाव

गर्मी का मौसम अपने साथ कइ बीमारियों को लेकर आता है। हीट स्ट्रोक, डायरिया, उल्टी, बेहोशी के साथ एक और जो सबसे कॉमन समस्या है वो है फूड पॉइजनिंग। दरअसल गर्मियों में तापमान बढ़ने के चलते बैक्टीरिया और खतरनाक सूक्ष्मजीव तेजी से पनपते हैं, जो खाने को आसानी से संक्रमित कर सकते हैं। खासकर बाहर बिकने वाले फूड्स। इसके अलावा अशुद्ध पानी भी फूड पॉइजिंग की वजह बन सकता है। फूड पॉइजनिंग किसी को भी हो सकती है, लेकिन छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्युनिटी वाले लोगों को इससे ज्यादा खतरा होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल दुनियाभर में तकरीबन 60 करोड़ लोग खानपान से होने वाली बीमारियों का शिकार होते हैं।

फूड पॉइजनिंग के बैक्टीरिया

फूड प्वॉइजनिंग के ज्यादातर केसेज में स्टेफायलोकोकस या ई कोलाई बैक्टीरिया का

इन्फेक्शन पाया जाता है। जो ब्लड, किडनी और तंत्रिका तंत्र पर सीधा असर डालता है। इसके अलावा सालमोनेला, स्टेफाइलोकोकाई और क्लॉसट्रिडियम बोट्यूलियम जैसे जर्म्स भी भोजन को संक्रमित करने का काम करते हैं। क्लॉसट्रिडियम बॉट्यूलियम द्वारा होने वाले इन्फेक्शन सबसे खतरनाक माना जाता है।

फूड पॉइजनिंग के कारण

-जानवर या मानव मल द्वारा संक्रमित पानी को फसलों की सिंचाई में इस्तेमाल करना।
-शौच के बाद हाथों को सही तरीके से न धोना।
-खाने के बर्तन गंदे होना।
-डेयरी प्रोडक्ट्स को रूम टेंपरेचर पर रखना।
-फोज़न फूड्स को सही से स्टोर न करना।
-सब्जियों व फलों को बिना धोए बनाना।
-नॉनवेज फूड्स को सही से न पकाना।
-संक्रमित और गंदे जल का सेवन करना।

फूड पॉइजनिंग के लक्षण

-पेट में तेज दर्द के साथ ऐंठन
डायरिया
-सिरदर्द, चक्कर, जी मचलाना और उल्टी होना
-बुखार के साथ ठंड लगना
-आंखों के आगे धुंधला छा जाना
-बेहोशी

फूड पॉइजनिंग होने पर करें ये उपाय

-खूब सारा पानी पीएं, जिससे डिहाइड्रेशन न हो।
-ओआरएस पिएं, जिससे उल्टी और दस्त की वजह से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स के असंतुलन को बराबर किया जा सके।
-सॉलिड फूड खाना अवॉयड करें। तला-भुना मसालेदार भोजन भी न खाएं।

दिल और दिमाग को बीमार बनाता है सोशल मीडिया

बीते वर्ष हुए एक रिसर्च की मानें तो जितने भी टिनेजर हैं जो आये दिन कम से कम तीन घंटे या उससे अधिक सोशल मीडिया का यूज करते हैं, उन स्टूडेंट्स में गुस्सा, दिमागी बीमारी जैसे लक्षण ज्यादातर देखने को मिलते हैं।

आजकल के मॉडर्न टाइम में स्टूडेंट्स से लेकर के वर्किंग लोगों की लाइफ सोशल मीडिया के चारों ओर घूमती नजर आती है। सोशल मीडिया के बिना रहना पड़ जाए तो लोग एंक्साइटी तक का शिकार हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सोशल मीडिया के ज्यादा इस्तेमाल को अवॉइड करना चाहिए।

नींद न आने की समस्या के हो सकते हैं शिकार

इस बात से तो आप भी बिल्कुल वाकिफ होंगें कि आजकल लगभग प्रत्येक व्यक्ति की ये हैबिट बन चुकी है कि सोने से पहले फोन का इस्तेमाल करना ही करना है। कभी कभी तो, ऐसा भी हो जाता है कि फोन चलाते चलाते कब घंटों निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता है, ऐसे में अनिद्रा अन्य स्लीप डिसऑर्डर के अलावा बॉडी से रिलेटेड कई सारी गंभीर समस्याएं होने के खतरा दो गुना ज्यादा बढ़ जाता है।

चलने लग जाते हैं ट्रेंडिंग की भेड़ चाल

दरअसल, सोशल मीडिया को एक बहुत मेन औजार भी माना जाता है, इसमें लोग उसी काम को करना पसंद करते हैं जिसका ट्रेंड चल रहा हो। कपड़ों से लेकर के खान पान, फैशन, मोबाइल फोन। सबकुछ ट्रेंडिंग और अपडेटेड वर्जन का ही चाहिए होता है। कई बार तो जब वो सोशल मीडिया में दिखने वाली वस्तुओं को नहीं ले पाते हैं तो इसका असर उनके दिमाग और बिहेवियर के उपर भी पड़ता है। जिससे वो धीरे धीरे अवसाद का शिकार हो जाते हैं।

खत्म हो जाती है प्राइवेसी

अक्सर देखा जाता है कि सोशल मीडिया पर अपनी पूरी इनफॉर्मेशन , जैसे कि अपडेटेड लोकेशन, डीपी यानी कि डिसप्ले पिक्चर, वीडियो तक शेयर कर देते हैं। जिससे हैकर्स जैसे लोग उनके इन्फो का गलत इस्तेमाल और मिस यूज भी कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेसी का मिसयूज और अन्य प्राइवेसी बाधित करने जैसी घटनाएं बढ़ने का खतरा डबल हो जाता है।

बढ़ जाता है मोटापा

फोन के अधिक इस्तेमाल और एडिक्शन की वजह से लोग अपने बेड से उठने में भी आलस करते हैं। इतना ही नहीं खाना खाते टाइम वीडियो और रील्स चल रहे होते हैं। ये सारी चीजें ओवरईट को बढ़ावा देती हैं। वहीं, फोन चलाते चलाते कब खाना धीरे धीरे एक्स्ट्रा हो जाता है ये भी पता नहीं चलता है।

बात करें सोशल मीडिया की तो ये तमाम सच से लेकर के झूठ इनफॉर्मेशन का भंडार होता है। वहीं, इसके ज्यादा इस्तेमाल से दिमाग में कई अलग अलग तरीके की इनफॉर्मेशन स्टोर होती जाती है। दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज आना लगभग खत्म से हो जाते हैं। क्योंकि व्यक्ति का मेन फोकस तो मेल, मैसेज, नोटिफिकेशन, कॉल, टेक्स्ट पर ही रहता है। जिससे शांति से विचार करने कि क्षमता लगभग खत्म हो जाती है।

लंबे समय तक एक ही तकिए का इस्तेमाल बना सकता है आपको बीमार

सोने के लिए तकिए का इस्तेमाल हर व्यक्ति करता है। लेकिन फिर भी अक्सर हमारा ख्याल तकिए की सफाई की तरफ कम ही जाता है। इनकी सफाई न होने के कारण, ये आपको कई तरह से बीमार कर सकता है, जिसका आपको पता भी नहीं चलता और आप अपने स्वास्थ्य को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं।

हेल्दी रहने के लिए आपके बिस्तर के साथ-साथ आपके तकियों का साफ रहना भी जरूरी है। उठते बैठते हमेशा इनका उपयोग होने से ये अनहाइजेनिक हो जाते हैं। ऐसे में सिर्फ तकिए का कवर चेंज कर देने से ही इनकी पूरी सफाई नहीं होती है। दिन और रात हमेशा उपयोग होने से इनमें मुंह के लार से लेकर पसीने की बूंद तक समाई रहती है, जो कवर बदल देने पर ऊपर से तो नहीं दिखाई देता, लेकिन अंदर से किटाणुओं से भरा रहता है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आपको अपने तकियों को कब

बदलना चाहिए और इससे कौन-कौन सी बीमारियां हो सकती हैं आइए जानें।

तकिया बदलना

तकिया हमारे शरीर के लिए सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। इसे लगाकर गर्दन और रीढ़ की हड्डी को सहारा और शरीर को आराम मिलता है। लेकिन इनकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है, जिसके बाद इनका उपयोग करने से आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानें इन्हें कब बदल लेना चाहिए।

-जब आपके तकिये का शेप बिगड़ने लगे तो समझ जाएं इन्हें बदलने की जरूरत है।
-अगर तकिए पर सोने से आपके सिर में लागतार दर्द होने की परेशानी होनी शुरू हो जाए।
-सुबह उठने पर पीठ और गर्दन में अकड़न और दर्द होने लगे।
-जब आपके तकिये की रुई में गांठें पड़ने लगें, तो समझ लीजिए कि आपके तकिए को बदलने का टाईम आ गया है।
-यदि आप अपने तकिए का उपयोग रोज लगातार कर रहे हैं, तो इसे कम से कम 18 महीने से 2 साल में जरूर बदल दें।
-अपने तकिए को एक बार फोल्ड करें और देखें यदि आपका तकिया तुरंत अपने शेप में आ जाता है तो इसका मतलब है ये अभी सही है। लेकिन अगर यह मुड़ा हुआ ही रह जाता है, तो इसका मतलब है कि आपके तकिए को बदलने का समय आ गया है।

तकियों से होने वाले इंफेक्शन

-बार-बार फ्लू, बुखार और खांसी तकिए के इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं।
-स्किन संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जैसे कि फेस एलर्जी।
-लगातार एक ही तकिए का उपयोग करने से आपको पीठ और गर्दन में अकड़न की समस्या भी हो सकती है।

एमबीए पेपर लीक कांड में अक्षय बम के कॉलेज को बचा रही सरकार : कांग्रेस

इंदौर। *देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के एमबीए पेपर लीक कांड को लेकर कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जिस आयडलिक कॉलेज से पेपर लीक हुआ वो अक्षय बम का है, सरकार उसे बचाने में लगी है। केंद्र ने कानून बनाया है कि पेपर लीक करने वाले पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना और 10 साल तक की सजा दी जानी चाहिए। लेकिन अक्षय बम के कॉलेज पर केवल 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।*

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की बैठक में सरकार की ओर से उच्च शिक्षा आयुक्त को भेजा गया। उन्होंने बैठक में शामिल सदस्यों से कहा कि नकारात्मक बात न करें और पेपर लीक करने वाले कॉलेज पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने विश्वविद्यालय में धारा 52 लगाने की मांग की गई। कांग्रेस इस मामले को विधानसभा में भी उठाएगी। इधर कांग्रेस नेताओं ने डीएवीवी गेट के पास अक्षय बम के पोस्टर लगाकर सवाल उठाया कि साइकिल पर चलने वाला करोड़पति कैसे बन गया। इस मामले में कांग्रेस लगातार जांच की मांग कर रही है। कांग्रेस ने इस मामले में पोल खोलो अभियान शुरू किया है। पोस्टर लगाने के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के बार प्रदर्शन किया।

ई-रिक्शा और बसों पर भी लगाए पोस्टर—कांग्रेस ने अक्षय बम पर सवाल उठाते पोस्टर डीएवीवी के साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, रीगल चौराहे सहित बसों और ई-रिक्शा के ऊपर लगाए गए हैं। इस मामले में डीएवीवी की कुलपति और रजिस्ट्रार को हटाने की मांग भी की जा रही है। पेपर लीक होने में इनकी भी लापरवाही है, आखिर पेपर कॉलेज के प्राचार्य के रूम में कैसे रखने दिए गए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अक्षय बम को इंदौर लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था। चुनाव से पहले आखिरी समय में उन्होंने नामांकन वापस ले लिया और भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस नया उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार नहीं पाई। जिसके बाद से कांग्रेस लगातार अक्षय बम पर निशाना साध रही है। पेपर लीक कांड में उनके कॉलेज का नाम सामने आने के बाद कांग्रेस लगातार इस मामले में प्रदेश सरकार और अक्षय पर निशाना साध रही है।

लोन एप की ब्लैकमेलिंग के कारण मैनेजर ने की खुदकुशी

रिश्तेदारों को भेज दिए थे अश्लील फोटो

इंदौर। लाजिस्टिक कंपनी के फेसेलिटी मैनेजर तारा सिंह की खुदकुशी केस में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। तारा सिंह को फटाफट ऋण बांटने वाले लोन एप की तरफ से धमकियां मिल रही थीं। ब्लैकमेलर ने उनका फोन हैक करके अश्लील फोटो बना लिए और रिश्तेदारों को भेज दिए थे। पुरारा (उत्तराखंड) निवासी 37 वर्षीय तारा सिंह थायत ने बुधवार को इंदौर स्थित महालक्ष्मीनगर स्थित होटल उत्सव इन में जहर खाकर खुदकुशी कर ली थी।

मोबाइल से खुला राज

रविवार को पुलिस ने स्वजन को थाने बुलाकर मोबाइल का पैटर्न लाक खोला तो पता चला उन्हें लोन एप क्विक कैश की तरफ से धमकियां मिल रही थीं। आरोपितों ने तारा सिंह के अश्लील फोटो (एडिटेड) बनाकर ऐसे अश्लील वाट्सएप ग्रुप में साझा कर दिए, जिनमें गुयाना, बांग्लादेश के लोग जुड़े हुए हैं। उस ग्रुप का स्क्रीन शाट लेकर तारा सिंह की बहन तारादेवी के फोन पर भी भेजा। इससे परेशान होकर तारा सिंह 12 जून को होटल पहुंचे और जहर खाकर जान दे दी। एसआइ महेंद्र मकाश्रे के मुताबिक, तारा सिंह को पाकिस्तान जनरेटेड नंबरों से काल आ रहे थे। कुछ आपत्तिजनक और धमकी भरे मैसेज भी मिले हैं।

साइबर एक्सपर्ट के मुताबिक, अवैध लोन एप को प्ले स्टोर से इंस्टाल करते समय कई तरह की परमिशन मांगी जाती है। शातिर अपराधी परमिशन देते ही संपर्क नंबरों की लिस्ट और फोटो गैलरी का एक्सेस ले लेते हैं। पूरा मोबाइल आरोपितों के कंट्रोल में आ जाता है। इसके बाद आरोपित मनमाफिक ब्याज और कर्ज वसूलना शुरू कर देते हैं। रुपये नहीं देने पर फोटो एडिट कर रिश्तेदार, परिचितों को फोटो और मैसेज भेजना शुरू कर देते हैं। तारा सिंह के स्वजन ने बताया कि वह घर से तीन लाख रुपये ले चुका थे। पुलिस साइबर एक्सपर्ट की मदद से जांच कर रही है।

कई मामले आ चुके हैं सामने

पूरे परिवार को लील चुके हैं लोन एप वाले लोन एप के कारण खुदकुशी का यह पहला मामला नहीं है। अगस्त-2022 में तो एक युवक ने पूरे परिवार सहित खुदकुशी की थी। इंदौर के भागीरथपुरा में रहने वाले अमित यादव ने पत्नी टीना, बेटी याना और बेटे दिव्यांश को जहर देकर मारने के बाद खुद भी फांसी लगा ली थी। अमित ने प्ले स्टोर से एप डाउनलोड कर ऋण लिया था।

कंपनी ने की धोखाधड़ी तीन पर केस, सिक्योरिटी बॉन्ड के नाम से रुपए लेने का आरोप

इंदौर। विजय नगर इलाके की एक आईटी कंपनी के सीईओ सहित तीन पर केस दर्ज किया गया है। पीड़ित लोगों ने आरोप लगाया है कि उनसे सिक्योरिटी बॉन्ड के नाम से रूपए लिये गए। इसके बाद आरोपी कंपनी बंद कर यहां से फरार हो गए। इस मामले में लिखित शिकायत पर जांच क बाद कार्रवाई की गई है।

टीआई सी बी सिंह के मुताबिक सदाशिव, हरिओम चंद्रवशी, अदिती चौकसे, गुंजन दीक्षित सहित अन्य लोगों ने रियल वर्ल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सीइओ सूर्य प्रकाश, अमित कुमार, रणविजय सिंह आफिस पता पीयू 4 स्कीम नंबर 54 के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज किया है। सदाशिव और अन्य लोगो ने अपनी शिकायत में बताया कि उक्त कंपनी के आफिस में करीब 300 लोग कार्यरत है। सबसे करीब 30 से 40 हजार रूपए की राशि सिक्योरिटी बॉन्ड के नाम से जमा करवाई गई। जिसमें कर्मचारियों से कहा गया कि 100 वर्किंग डेज के बाद सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन 70 दिनों में ही कंपनी फरार हो गई। कर्मचारियों की नियुक्ति 11 मार्च से की गई। जिसमें अलग अलग समूह बनाकर उनसे काम कराया जा रहा था। जिसमें कुछ कर्मचारियों से आफिस बुलाकर और कुछ से ऑनलाइन काम कराया जा रहा था।

गुंडे को घेरकर उतारा मौत के घाट

पुराने मामले में समझौते के लिए मिलने के बहाने बुलाया था

इंदौर। *एरोड्रम इलाके में गैंगवार की बात सामने आई है। जेल से छूटे गुंडे की दूसरी गैंग ने हत्या कर दी। 6 से ज्यादा आरोपियों ने मिलकर उसे मारा। बता दें कि 24 घंटे में हत्या का यह दूसरा मामला है। इससे पहले शनिवार रात भी छत्रीपुरा के अर्जुनपुरा मल्टी में युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी।*

पुलिस ने बताया परिहार कॉलोनी का रहने वाला रोहित पिता जितेंद्र कसेरा कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा था। उसके खिलाफ नितिन उर्फ जॉन यादव के दोस्त पर हमला करने का आरोप था। एरोड्रम थाने पर केस दर्ज है। जेल से छूटने के बाद रोहित ने फरियादी से समझौता का दबाव बनाया था। इस पर नितिन के दोस्त ने उसे रविवार रात बातचीत के लिए बुलाया। जैसे ही रोहित पहुंचा, वहां 6 से अधिक लोगों ने हथियारों से हमला कर दिया। घटनास्थल से रोहित को बेसुध हालत में अरविंदो हॉस्पिटल लाया गया, यहां मृत घोषित कर दिया गया। आरोपियों की तलाश की जा रही है। अब तक 4 के नाम सामने आए हैं, उसमें आरोपी नितिन यादव शामिल है। पुलिस ने कहा कि रोहित (मृतक) और नितिन की वर्चस्व को लेकर टसल पुरानी है। दोनों के खिलाफ केस दर्ज हैं। गैंगवार से जुड़ा मामला है।

करीब 6 केस दर्ज थे रोहित पर

पुलिस ने बताया मृत रोहित भी क्रिमिनल पृष्ठभूमि का था। उसके खिलाफ भी 6 से ज्यादा केस दर्ज थे। उसकी हत्या नितिन यादव उर्फ जॉन निवासी भोलेनाथ कॉलोनी का नाम आया है। कुछ दिनों पहले नितिन के दोस्त और रोहित में विवाद हुआ था। उसके बाद से दोनों ग्रुप में तनातनी थी। मामले में राजनीतिक संरक्षण की बात सामने आई है।

हनी ट्रेप में शामिल रह चुका है हत्या का आरोपी

रोहित हत्याकांड में शामिल आरोपी नितिन उर्फ जॉन पर पूर्व में हनी ट्रेप का केस भी दर्ज हो चुका है। उसमें एक बिल्डर को फंसाया गया था। इसी केस में एक युवती के सुसाइड में भी उसका नाम जुड़ चुका है। सुसाइड नोट में जॉन का नाम था। अब पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी जयश्री जैन द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स 13, प्रेस कॉम्प्लेक्स ए.बी. रोड इंदौर से मुद्रित एवं 22, प्रेस काम्पलेक्स, प्रेस हाऊस, ए.बी. रोड इंदौर 452008 से प्रकाशित। प्रधान संपादक- डॉ. राजेश जैन, मो. 9425322301 (डाक पंजीयन MP/IDC/1462/2016-2019)